PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 230
दि. 24.05.2026, रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

टुकड़ा-टुकड़ा बढ़ती महंगाई ने बढ़ाई जनता की बेचैनी 10 दिनों में तीसरी बार महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

नई दिल्ली/मुंबई। देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा एक बार फिर ईंधन के दाम बढ़ाए जाने के बाद अब महंगाई के और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई में पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 108 रुपये 49 पैसे तक पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के बाद यह 95 रुपये 02 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बीते 10 दिनों में यह तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों ने न केवल आम उपभोक्ताओं बल्कि परिवहन क्षेत्र, व्यापारियों और किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। देश की प्रमुख तेल कंपनियां Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum द्वारा जारी नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। मुंबई समेत कई महानगरों में पेट्रोल अब 109 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक आपूर्ति दबाव और कर संरचना के कारण आने वाले दिनों में कीमतों में और वृद्धि हो सकती है।

लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों का असर अब सीधे रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। परिवहन लागत बढ़ने से फल, सब्जियां, दूध, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। व्यापारिक संगठनों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि डीजल महंगा होने से माल ढुलाई की लागत तेजी से बढ़ रही है, जिसका बोझ अंततः आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कई शहरों में निजी टैक्सी सेवाओं ने किराए बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और ट्रैवल बस संचालक भी नए किराया ढांचे की तैयारी में

जुट गए हैं।

विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जनता पहले से ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के दबाव में है, ऐसे समय में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आम लोगों की कमर तोड़ रही है। उनका आरोप है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से दाम बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है।

पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब केवल 10 दिनों के भीतर तीन बार ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई हों। उनके अनुसार सरकार एकमुश्त बड़ी बढ़ोतरी करने के बजाय छोटे-छोटे चरणों में दाम बढ़ा रही है, जिससे लोगों में असमंजस और बेचैनी का माहौल बन रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों के कारण कई जगह लोग एहतियात के तौर पर अपने वाहन फुल टैंक करा रहे हैं। इससे कुछ पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है और ईंधन की उपलब्धता को लेकर चिंताएं भी सामने आने लगी हैं।

पेट्रोलियम क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। मार्च और मई के दौरान कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में पहले ही कई बार इजाफा किया जा चुका है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि भविष्य में पेट्रोल और डीजल के दामों में 14 से 15 रुपये प्रति लीटर तक की और वृद्धि संभव है, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।

ईंधन कीमतों में तेजी का असर महाराष्ट्र में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राज्य के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की मांग अचानक बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए Devendra Fadnavis ने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में ईंधन की मांग सामान्य स्तर से 20 से 30 प्रतिशत तक अधिक हो गई है, जो असामान्य स्थिति मानी जा रही है। उन्होंने संकेत दिए कि कहीं किसानों के नाम पर पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी तो नहीं की जा रही, इसकी जांच कराई जा रही है।

शिर्डी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष ईंधन की जरूरत का अनुमान प्रशासन के पास रहता है, लेकिन इस बार अचानक मांग में वृद्धि ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने जिलाधिकारियों और विभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को खेती संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक डीजल समय पर उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और प्रशासन इस विषय पर विशेष निगरानी रखेगा।

राज्य के ग्रामीण इलाकों से ईंधन उपलब्ध न होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। कुछ जिलों में डीजल वितरण के दौरान वाहनों की आरसी बुक की जांच शुरू की गई है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही ईंधन मिल सके। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कृत्रिम रूप से ईंधन संकट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि आपूर्ति श्रृंखला बाधित न हो और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी केवल परिवहन तक सीमित असर नहीं डालती, बल्कि इसका प्रभाव पूरे आर्थिक तंत्र पर पड़ता है। कृषि लागत, निर्माण कार्य, सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक उत्पादन और घरेलू खर्च सभी इससे प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बढ़ती महंगाई अतिरिक्त आर्थिक दबाव पैदा कर रही है।

देश में पहले ही खाद्य वस्तुओं और दैनिक उपयोग की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में यदि ईंधन दरों में और वृद्धि होती है तो इसका असर बाजार, परिवहन और घरेलू बजट पर और गहराई से दिखाई दे सकता है। फिलहाल आम जनता की नजर सरकार और तेल कंपनियों के अगले फैसलों पर टिकी हुई है।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को नई गति, पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो

नई दिल्ली। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कूटनीतिक पहल के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा साझेदारी को लेकर लगातार संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस मुलाकात को "भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और विकास के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री का स्वागत करना उनके लिए प्रसन्नता की बात है और दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है।

बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग, व्यापारिक संबंधों, तकनीकी साझेदारी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। अमेरिकी पक्ष ने भी भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदार के रूप में देखते हुए विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में राजदूत सर्जियो गोर और उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर शामिल थे।

भारत में अमेरिकी राजदूत Sergio Gor ने इस बैठक को बेहद "सार्थक" बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत में सुरक्षा, व्यापार

और अत्याधुनिक तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर सकारात्मक चर्चा हुई। राजदूत ने संकेत दिया कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय संवाद और बढ़ सकता है, जिससे रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन बदलाव और तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों ही देश एक-दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाकर वैश्विक संतुलन में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहते हैं। खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध रक्षा समझौतों, तकनीकी सहयोग, अंतरिक्ष साझेदारी और व्यापारिक निवेश के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय संवाद का उद्देश्य न केवल द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है, बल्कि वैश्विक चुनौतियों—जैसे आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा—से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करना भी है।

इस मुलाकात को कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यह संकेत देती है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका अपने संबंधों को केवल रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं रखकर उसे और व्यापक वैश्विक सहयोग के स्तर तक ले जाना चाहते हैं। बैठक के बाद दोनों पक्षों की ओर से दिए गए सकारात्मक बयानों से यह स्पष्ट है कि दोनों देश भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस मुलाकात के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि भारत-अमेरिका संबंधों में तकनीक, रक्षा और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को लेकर नए समझौते और पहल देखने को मिल सकती हैं, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और अधिक मजबूत होगी।

नशे के खिलाफ केरल का बड़ा युद्ध, 'ऑपरेशन तूफान' से ड्रग माफियाओं पर कसेगा शिकंजा

तिरुवनंतपुरम। दक्षिण भारत के राज्यों में तेजी से फैलते सिंथेटिक ड्रग्स और नशीले पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ अब केरल सरकार ने बड़ा और निर्णायक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। Ramesh Chennithala ने राज्य में नशा तस्करों और ड्रग माफियाओं के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के लिए 'ऑपरेशन तूफान – द नार्को हंट' नामक विशेष अभियान की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना नहीं, बल्कि राज्य में सक्रिय पूरे ड्रग नेटवर्क और उसके आर्थिक-सामाजिक प्रभाव को जड़ से खत्म करना है।

गृह मंत्री ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी पहली उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस विशेष अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक जून से शुरू होने वाला यह अभियान राज्यव्यापी स्तर पर चलाया जाएगा और इसमें पुलिस, नारकोटिक्स विभाग, खुफिया एजेंसियों तथा अन्य राज्यों की कानून-व्यवस्था एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। खास बात यह है कि यह अभियान उसी दिन शुरू होगा जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुलेंगे। सरकार का मानना है कि

स्कूल और कॉलेजों के आसपास सक्रिय ड्रग नेटवर्क युवाओं और छात्रों को सबसे अधिक निशाना बना रहे हैं, इसलिए अभियान का प्राथमिक फोकस शैक्षणिक संस्थानों के आसपास चल रहे नशा कारोबार को खत्म करना होगा।

Ramesh Chennithala ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि स्कूलों और कॉलेजों के आसपास तंबाकू, मादक पदार्थ और सिंथेटिक ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और यह केवल कानून-व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक और पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर संकट बनता जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार इस समस्या को केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसे सामाजिक जागरूकता और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से भी नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।

गृह मंत्री के अनुसार आने वाले दिनों में पुलिस राज्यभर में लगातार विशेष छापेमारी अभियान चलाएगी। ड्रग्स की सप्लाई चेन, वितरण नेटवर्क और बार-बार अपराध करने वाले तस्करों की पहचान कर उनके खिलाफ संगठित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़े हर व्यक्ति को पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा और किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि राज्य के भीतर और बाहर से संचालित नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि केरल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान सिंथेटिक ड्रग्स का उपयोग और तस्करी तेजी से बढ़ी है। खासतौर पर एमडीएमए और अन्य केमिकल आधारित ड्रग्स के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार युवाओं और छात्रों के बीच इन नशीले पदार्थों की पहुंच बढ़ना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। कई मामलों में ड्रग नेटवर्क सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी सक्रिय पाए गए हैं। यही कारण है कि सरकार अब इस खतरे को केवल अपराध नहीं बल्कि सामाजिक आपदा के रूप में देख रही है।

सरकार का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसीलिए गृह मंत्री ने मीडिया, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि समाज जागरूक होगा और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना समय पर देगा, तभी ड्रग माफियाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास नशीली गतिविधियों पर नजर रखें और पुलिस को जानकारी देने में संकोच न करें।

इस अभियान को लेकर पुलिस विभाग में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार विभिन्न जिलों में विशेष एंटी-नारकोटिक टीमें गठित की जा रही हैं। स्कूलों और कॉलेजों के आसपास निगरानी बढ़ाई जाएगी। संवेदनशील इलाकों में गुप्त निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और डिजिटल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया जा सकता है।

'भव्य योजना' से भारत में औद्योगिक क्रांति की नई तैयारी, 100 इंडस्ट्रियल पार्कों के जरिए निवेश और रोजगार को बढ़ावा

नई दिल्ली। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति देने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ी औद्योगिक पहल की घोषणा की है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal ने शनिवार को 'भव्य (भारत औद्योगिक विकास योजना)' के दिशा-निर्देशों को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पूरे देश में 100 आधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए सरकार ने 33,660 करोड़ का विशाल वित्तीय परिव्यय मंजूर किया है।

सरकार का मानना है कि यह योजना भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी। योजना के तहत विकसित होने वाले इंडस्ट्रियल पार्क 'प्लग-एंड-प्ले' मॉडल पर आधारित होंगे, यानी उद्योगों को पहले से तैयार भूमि, बिजली, पानी, सड़क, लॉजिस्टिक्स और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि कंपनियां बिना लंबी प्रक्रिया के सीधे उत्पादन शुरू कर सकें।

केंद्र सरकार इन औद्योगिक पार्कों को राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित करेगी। यह

मॉडल केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को मजबूत करते हुए निवेश को अधिक सुगम और तेज बनाने की दिशा में तैयार किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे राज्यों में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अधिक से अधिक निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें तैयार इकोसिस्टम में तुरंत उत्पादन शुरू करने का अवसर मिलेगा। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका चरणबद्ध क्रियान्वयन है। Piyush Goyal ने जानकारी दी कि पहले चरण में अगले दो महीनों के भीतर 20 इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद अगले दो महीनों में 30 और पार्कों के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। शेष 50 पार्क बाद के चरण में विकसित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि शुरुआती 50 पार्कों के लिए तेजी से प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यान्वयन को गति दी जाए।

केंद्र सरकार अगले चार महीनों के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। इस प्रक्रिया के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास हो और किसी भी क्षेत्र को विकास की दौड़ में पीछे न रहना पड़े। नीति निर्माताओं का मानना है कि इससे पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और पिछड़े क्षेत्रों में भी निवेश का नया मार्ग खुलेगा।

'भव्य योजना' का मुख्य उद्देश्य देश में एक मजबूत और आधुनिक औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां उद्योगों को जमीन अधिग्रहण, अनुमति प्रक्रियाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जैसी जटिलताओं से नहीं जूझना पड़े। इसके बजाय उन्हें एक तैयार ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उत्पादन की शुरुआत में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। इससे न केवल निवेश की गति बढ़ेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना भारत की औद्योगिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। अब तक जहां औद्योगिक विकास अक्सर धीमी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और बिखरे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बाधित होता रहा है, वहीं 'भव्य योजना' इन चुनौतियों को दूर करने की दिशा में एक संरचनात्मक सुधार के रूप में देखी जा रही है। योजना के तहत विकसित किए जाने वाले पार्कों में आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रीन एनर्जी समाधान और पर्यावरण अनुकूल निर्माण मानकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि औद्योगिक विकास केवल तेज ही नहीं, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण-संतुलित भी हो। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो भारत में विदेशी निवेश (FDI) में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। वैश्विक कंपनियां ऐसे देशों की ओर आकर्षित होती हैं जहां तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान व्यापारिक माहौल उपलब्ध हो। 'भव्य योजना' इसी दिशा में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करती है। इसके अलावा, इस योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इंडस्ट्रियल पार्कों के आसपास छोटे व्यवसाय, सेवा क्षेत्र और सप्लाई चेन नेटवर्क विकसित होंगे, जिससे अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह योजना आर्थिक गतिविधियों का नया केंद्र बन सकती है।

सरकार का दावा है कि यह योजना 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों को भी मजबूत करेगी। घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात को नई गति मिलेगी। इससे भारत वैश्विक सप्लाई चेन में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। फिलहाल इस योजना को लेकर उद्योग जगत में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। व्यापारिक संगठनों का मानना है कि यदि भूमि आवंटन, अनुमोदन प्रक्रिया और इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर उपलब्ध कराया गया, तो यह योजना भारत के औद्योगिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। कुल मिलाकर 'भव्य योजना' न केवल एक निवेश कार्यक्रम है, बल्कि यह भारत के औद्योगिक भविष्य को नए स्वरूप में ढालने की एक व्यापक रणनीति भी है, जिसका असर आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक संरचना पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है।

संपादकीय

देखभाल करना नैतिक कानूनी जिम्मेदारी

संवेदनाओं के क्षरण व आत्मकेंद्रित होती नई पीढ़ी के दौर में मां-बाप की बेकद्री विचलित करने वाली है। यह विडंबना ही है कि उन मां-बाप की देखभाल करने का निर्देश अदालत को देना पड़ रहा है, जिनका ऋण वे कभी चुका ही नहीं सकते। मां के रक्त से सींचे गए और पिता की पसीने से पले-बढ़े बेटे से यदि अदालत को कहना पड़े कि 'मां को घर में रहने के लिये एक कमरा, अलग बाथरूम और बुनियादी सुविधाएं दी जाएं', तो यह बात शर्मसार करने वाला है। जिस मां ने नौ माह तक बेटे को अपने पेट में पाला, उसे घर में रहने देने के लिये अदालत को निर्देश देना पड़े, इससे बड़ा कृतघ्नता का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। भले ही यह कोर्ट का आदेश हो, लेकिन यह एक अलिखित नैतिक दायित्व पहले से ही है। निश्चय ही यह घटनाक्रम हमारे समाज की बेहद कष्टदायक होती तसवीर को ही उकेरता है। सामान्य तौर पर मां-बाप अपना पेट काटकर, अपने सुख-सुविधाओं पर समझौता कर, बच्चों को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। एक मां-बाप ही होते हैं जो सच्चे मन से अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं। निस्संदेह, ऐसी पढ़ी-लिखी संतानों से अनपढ़ संतानें बेहतर हैं, जो कम से कम अपने वृद्ध माता-पिता के पास रहकर उनका ख्याल तो रखती हैं। यह सवाल परेशान करने वाला है कि जिस समाज में 'मातृ देवो भव' की सर्वस्वीकार्य मान्यता रही हो, वहां ये कैसी कलयुगी संतानें जन्म ले रही हैं? मां-बाप की बेकद्री की यह अकेली कहानी नहीं है, हर रोज अखबारों में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें धन-संपत्ति के लिये मां-बाप से क्रूरता की जा रही होती है। निस्संदेह, यदि उनकी अवहेलना व उत्पीड़न का यह क्रम यूं ही चलता रहा तो बहुत संभव है भारत में भी पश्चिमी देशों जैस चलन शुरू हो जाएगा, जहां मां-बाप बच्चों को होश संभालने के बाद ही उन्हें पैरों पर खड़ा होने के लिये चलता कर देते हैं।

दरअसल, पश्चिमी देशों में मां-बाप मानकर चलते हैं कि बड़े होकर बच्चों ने उनकी देखभाल नहीं करनी, अतः इनसे पहले ही किनारा कर लो। आधुनिकता व तरक्की की लाख इबारतें लिख ली जाएं, भारतीय समाज कभी पश्चिमी समाज की तर्ज पर नहीं चल सकता। भारत श्रवण कुमार का देश है और आज भी अधिसंख्य संतानें अपने मातृ-पितृ ऋण उतारती हैं। उनका ख्याल रखती हैं। विकृतियां महानगरीय संस्कृति की भी देन हैं। बच्चों की भी अपनी दुश्वारियां हैं। फिर भी भारतीय संस्कृति में वो शक्ति है जो पारिवारिक मूल्यों को सींचती है। बहरहाल, माता-पिता की सेवा-सम्मान व बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना महज एक सांस्कृतिक दिखावा नहीं है बल्कि संतानों का नैतिक-कानूनी दायित्व भी है। हाल ही में कोर्ट ने जिस घर में बेटे को वृद्ध मां को एक कमरा आदि देने को कहा, वह मकान वृद्धा के दिवंगत पति द्वारा ही बनाया गया था। जिसमें अपना हक पाने हेतु उसे न्यायिक हस्तक्षेप का सहारा लेना पड़ा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि किसी वृद्ध मां को आश्रय और आत्म स्वाभिमान हेतु बच्चों के खिलाफ कोर्ट-कचहरी करनी पड़े। निस्संदेह, यह उस भारतीय संयुक्त परिवार परंपरा का पराभव ही है जिसकी मिसाल पश्चिमी भोगवादी संस्कृति के अगुवा दिया करते थे। यहां न्यायालय के संवेदनशील व न्यायपूर्ण निर्णय की मुक्त कंठ से सराहना करनी होगी, जिसमें कोर्ट ने निर्णय के खिलाफ दी गई पुत्र की याचिका को खारिज कर जुर्माना लगाया। यह कष्टकारी ही है कि देशभर की अदालतें परित्यक्त-प्रताड़ित माता-पिता से जुड़े विवादों का सामना कर रही हैं। न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों ने दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को बेदखल करने तक के आदेश दिए हैं। अदालतों द्वारा माता-पिता द्वारा अर्जित संपत्ति पर उनके अधिकारों को बरकरार रखने ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को सुदृढ़ ही किया है। न्यायपालिका ने संपत्ति के अधिकार के साथ ही कल्याण संबंधी चिंताओं को भी सावधानीपूर्वक संतुलित किया है। न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पारिवारिक झगड़ों में कानून का दुरुपयोग न हो। लेकिन फिर भी संकट का समाधान सिर्फ कानून से संभव नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला संदेश देता है कि विरासत पर बातचीत हो सकती है, लेकिन मानवता पर नहीं।

तारीख पर तारीख से मुक्ति की पहल

> "यदि हम स्वचालित प्रणालियों और जवाबदेह कार्यशैली को अपनाते हैं, तो न्याय का रथ तारीखों के बोझ से मुक्त होकर मानवीय गरिमा और त्वरित तर्क के पथ पर अग्रसर होगा। यह केवल एक आदेश नहीं, बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली के पुनरुद्धार का एक महा-संकल्प है।

न्याय के गलियारों में गूंजती 'तारीख पर तारीख' की प्रतिध्वनि दरअसल उस आम आदमी की सिसकी है, जिसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता फाइलों के बोझ तले दम तोड़ रही है। फिल्म 'दामिनी' का वह मशहूर संवाद– 'तारीख पर तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला' महज एक फिल्मी लाइन नहीं, बल्कि भारत की अदालतों की उस कड़वी हकीकत का जीवंत दस्तावेज़ है, जिससे हर रोज़ देश का आम नागरिक गुज़रता है। 'न्याय में देरी, न्याय से वंचित होना है'—यह कहावत भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी चुनौती रही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विसंगति को जड़ से मिटाने के लिए एक क्रांतिकारी पहल की है।

हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने स्पष्ट किया है कि जमानत याचिकाओं में अनावश्यक देरी न केवल कानूनी विफलता है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' के ऐतिहासिक मामले में स्थापित यह सिद्धांत कि 'कानूनी प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए', आज भी हमारी न्यायिक शुचिता की कसौटी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे बड़े न्यायालयों में संसाधनों की भारी कमी और न्यायिक ढांचे पर अत्यधिक दबाव चिंताजनक है, जहां एक न्यायाधीश को प्रतिदिन औसतन 200 जमानत याचिकाओं की सुनवाई करनी पड़ती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार जायसवाल ने 'तारीख पर तारीख' की संस्कृति पर तीखी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि इस न्यायिक देरी का अनुचित लाभ उठाकर कई दागी व्यक्ति राजनीति के शीर्ष पदों तक पहुंच जाते हैं। न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि देरी के लिए केवल न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि पुलिस द्वारा समय पर फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों को पेश न करना भी समान रूप से जिम्मेदार है।

कानूनी परिप्रेक्ष्य में 'स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बालचंद (1977)' के तहत जस्टिस कृष्ण अय्यर का यह सिद्धांत सर्वोपरि है कि 'जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद'। भारतीय न्यायशास्त्र के अनुसार जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष है। इसके बावजूद, 'तारीख पर तारीख' के चक्रव्यूह में फंसकर विचाराधीन कैदी बिना किसी अपराध के वर्षों जेल में काट देते हैं। इसी न्यायिक जड़ता को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब जमानत मामलों को हर हफ्ते या अधिकतम दो हफ्ते में लिस्ट करने का निर्देश दिया है। 'सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022)' मामले में भी अदालत ने साफ कहा था कि जमानत में देरी नागरिक की गरिमा पर सीधी चोट है।

विकसित देशों में जमानत प्रक्रिया भारत की तुलना में अधिक त्वरित और तकनीक-केंद्रित है। यूनाइटेड किंगडम में 'बेल एक्ट 1976' के तहत जमानत एक वैधानिक अधिकार है, जिस पर अदालतें कुछ ही घंटों या दिनों में निर्णय लेती हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका में 'एक्चुअरियल रिस्क असेसमेंट' और एल्गोरिदम जैसे तकनीकी टूल्स का उपयोग न्यायाधीशों को वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने और प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। इसी दिशा में भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी अब 'ऑटोमेटिक लिस्टिंग सिस्टम' पर जोर दे रहा है।

इस न्यायिक जड़ता को तोड़ने के लिए 'मद्रास उच्च न्यायालय' की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय मॉडल बनाना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु 'विशेष जमानत अदालतें' या समर्पित 'स्वतंत्रता बेंच' का गठन समय की मांग है। सुधार का दूसरा अनिवार्य स्तंभ 'संस्थागत जवाबदेही' है। जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष के लिए जवाब दाखिल करने हेतु 72 घंटे से 7 दिनों की सख्त समय-सीमा तय हो। सरकारी पक्ष द्वारा समय मांगे जाने पर 'कॉस्ट इम्पाउन्डिंग' जैसे दंडात्मक उपाय लागू होने चाहिए। साथ ही, अधूरी चार्जशीट और विलंबित जांच पर अंकुश लगाना होगा, जो 'तारीख पर तारीख' का मुख्य कारण हैं।

जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक ऐसा 'केस मैनेजमेंट सिस्टम' विकसित हो, जहां हर मुकदमे का 'लाइफ-साइकिल' पहले से निर्धारित हो। ई-फाइलिंग और अनिवार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रशासनिक एवं भौतिक पेशी की बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। न्याय को मानवीय संवेदनाओं की कसौटी पर कसना होगा। भारी मुचलके न भर पाने के कारण जेलों में बंद गरीब कैदियों के लिए 'पर्सनल बॉन्ड' को प्राथमिकता देना एक साहसी कदम होगा। जब जांच, तकनीक और मानवीय गरिमा का संगम होगा, तभी न्याय की ड्योढ़ी पर आम आदमी का विश्वास बहाल हो सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप लोकतंत्र की जीवंतता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रतीक है। 'तारीख पर तारीख' के फिल्मी संवाद को हकीकत में बदलने के लिए प्रशासनिक जटिलताओं को खत्म करना और 'जेल नहीं, जमानत' के सिद्धांत को धरातल पर उतारना अनिवार्य है। यदि हम स्वचालित प्रणालियों और जवाबदेह कार्यशैली को अपनाते हैं, तो न्याय का रथ तारीखों के बोझ से मुक्त होकर मानवीय गरिमा और त्वरित तर्क के पथ पर अग्रसर होगा। यह केवल एक आदेश नहीं, बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली के पुनरुद्धार का एक महा-संकल्प है।

प्रेरणा

मानवता की मूरत बनी जेन एडम्स

संसार में कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं, जिनका जीवन केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि वे दूसरों के दुःख हरने के लिए धरती पर आते हैं। उनका हृदय इतना विशाल होता है कि उसमें संपूर्ण मानवता के लिए करुणा उमड़ती रहती है। ऐसे लोग अपने सुख-सुविधाओं को त्यागकर समाज के कमजोर, पीड़ित और असहाय लोगों की सेवा में जीवन समर्पित कर देते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता धन, शक्ति और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और प्रेम में होती है। ऐसी ही महान आत्मा थीं Jane Addams, जिन्हें संसार ने करुणा की प्रतिमा और देहधारी देवी के रूप में सम्मान दिया।

जेन एडम्स का जन्म अमेरिका के एक अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध सीनेटर और बड़े उद्योगपति थे। घर में धन-दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता अपनी इकलौती पुत्री के लिए अपार संपत्ति एकत्र कर रहे थे, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। लेकिन जेन एडम्स बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग थीं। उनका मन ऐश्वर्य और विलासिता में नहीं लगता था। वे छोटी उम्र से ही गंभीर विचारों वाली, संवेदनशील और अध्ययनशील थीं। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। वे महान विचारकों, दार्शनिकों और समाज सुधारकों के जीवन को पढ़तीं और मानवता के बारे में चिंतन करती रहती थीं।

जब वे युवावस्था में पहुंचीं, तब उन्होंने समाज की वास्तविक स्थिति को बहुत करीब से देखा। उन्होंने महसूस किया कि संसार में लाखों लोग ऐसे हैं, जिनके पास भोजन, कपड़े और रहने तक की सुविधा नहीं है। वे गरीब, बीमार और असहाय लोग जीवनभर संघर्ष करते रहते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग अत्यधिक संपत्ति में जीते हैं। यह असमानता उनके हृदय को भीतर तक विचलित करती थी। धीरे-धीरे उनके भीतर यह भावना मजबूत हो गई कि मनुष्य का जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी जीना चाहिए।

पिता के निधन के बाद उनके सामने अपार संपत्ति थी। वे चाहतीं तो विलासिता और आराम से भरा जीवन जी सकती थीं। लेकिन उन्होंने एक अलग मार्ग चुना। उन्होंने निश्चय किया कि यह संपत्ति केवल उनके व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि मानव सेवा के लिए उपयोग होगी। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति बेच दी और उसी धन से अमेरिका में एक मानव सेवा केंद्र की स्थापना की, जिसे "डल हाउस" के नाम से जाना गया। यह स्थान केवल एक संस्था नहीं थी, बल्कि हजारों गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए जीवन का सहारा बन गया।

डल हाउस का उद्देश्य गरीब लोगों को सस्ता भोजन और सस्ता निवास उपलब्ध कराना था, लेकिन इसके पीछे जेन एडम्स की सोच कहीं अधिक गहरी थी। वे चाहती थीं कि समाज के उपेक्षित लोग केवल जीवित ही न रहें, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना सीखें। इसलिए वहां शिक्षा, नैतिकता, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। जो लोग वहां आते, उन्हें केवल सहायता ही नहीं मिलती, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा भी मिलती थी।

धीरे-धीरे डल हाउस एक आंदोलन बन गया। हजारों लोग वहां आने लगे और लाखों लोग जेन एडम्स के विचारों से प्रभावित हुए। उनकी सादगी, करुणा और त्याग देखकर लोग उनके सहयोगी बनते चले गए। जेन एडम्स स्वयं बहुत साधारण जीवन जीती थीं। उन्होंने कभी अपने लिए वैभव नहीं चाहा। वे दिन-रात जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगी रहती थीं। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना था।

उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से अनेक कार्य किए। उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। गरीब महिलाओं को शिक्षा और सम्मान नहीं मिलता था। वे आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर थीं और अनेक प्रकार के अत्याचार सहने को मजबूर थीं। जेन एडम्स ने महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र, प्रशिक्षण संस्थान और सहायता कार्यक्रम शुरू किए। वे मानती थीं कि यदि महिला सशक्त होगी, तो पूरा समाज मजबूत होगा। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

बच्चों के प्रति भी उनका प्रेम असाधारण था। उस समय बाल श्रम एक बड़ी समस्या थी। छोटे-छोटे बच्चे कारखानों और फैक्ट्रियों में कठिन काम करने के लिए मजबूर थे। जेन एडम्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए कई अभियान चलाए। वे चाहती थीं कि हर बच्चा शिक्षा पाए, स्वस्थ रहे और भयमुक्त जीवन जी सके। उनके प्रयासों से हजारों बच्चों का जीवन बदला।

उन्होंने विकलांगों और रोगियों की सेवा को भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। समाज जिन लोगों को बोझ समझता था, जेन एडम्स उन्हें ईश्वर का अंश मानती थीं। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित कीं, जहां उनकी देखभाल, चिकित्सा और पुनर्वास की व्यवस्था की गई। वे हर व्यक्ति के भीतर मानवता और सम्मान को देखती थीं। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वही है, जिसमें पीड़ितों की सेवा की जाए।

जेन एडम्स केवल समाज सेवा तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने विश्व शांति के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे युद्ध और हिंसा की कट्टर विरोधी थीं। उनका विश्वास था कि युद्ध मानवता को केवल विनाश देता है। उन्होंने महिलाओं को संगठित कर शांति और मानवाधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय महिला लीग की स्थापना की। इस संगठन ने विश्वभर में महिलाओं को नई चेतना और शक्ति प्रदान की। जेन एडम्स का संदेश स्पष्ट था कि प्रेम, सहानुभूति और करुणा ही संसार को बेहतर बना सकते हैं। उनके महान कार्यों को देखते हुए उन्हें विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लेकिन उनके लिए यह सम्मान व्यक्तिगत गौरव का विषय नहीं था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार में मिली पूरी राशि भी मानव सेवा के कार्यों के लिए दान कर दी। यह घटना उनके त्याग और निस्वार्थ भाव का सबसे बड़ा प्रमाण थी। आज के समय में जब लोग छोटे-छोटे लाभ के लिए भी स्वार्थ में डूब जाते हैं, वहां जेन एडम्स ने अपनी हर उपलब्धि को समाज के नाम समर्पित कर दिया। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। उनके लिए पूरी मानवता ही उनका परिवार थी। वे हर पीड़ित व्यक्ति में अपने प्रियजन का रूप देखती थीं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने में है। जिसने अपने जीवन को मानवता की सेवा में अर्पित कर दिया, वही वास्तव में अमर हो जाता है। आज संसार में धनवान लोग बहुत हैं, लेकिन जेन एडम्स जैसे त्यागी और करुणामयी लोग बहुत दुर्लभ हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की महानता उसके धन में नहीं, बल्कि उसके हृदय की विशालता में होती है।

फिर से न उभरने पाएं माओवादी

माओवाद का जहर निकालने के बाद मोदी सरकार अब प्रभावित इलाकों की सुरक्षा और वहां विकास सुनिश्चित करने में जुट गई है। बीते दिनों बस्तर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यहां विकास न पहुंचने का कारण माओवाद को बताते हुए कहा कि गैर-भाजपा सरकारों ने तो माओवाद मुक्त अभियान में हमारा सहयोग किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया।

इस पर विचार करना आवश्यक है कि 1960 के दशक में बंगाल के नक्सलबाड़ी से उठा ये बवंडर कैसे 14 राज्यों के लगभग 150 जिलों तक फैल गया? कैसे माओवादी तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक लाल गलियारा बनाने में जुटे? आखिर वे कौन सरकारें थीं, जिन्होंने हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं करने वाले माओवादियों को फलने-फूलने दिया और उन्हें बिगड़ैल बच्चा कहकर आगे बढ़ाया?

यह अकारण नहीं है कि पीएम मोदी कांग्रेस को माओवाद समर्थक बताते हैं। कांग्रेस का इतिहास माओवाद के समर्थन का भी रहा है। वह माओवाद को एक सामाजिक-आर्थिक समस्या बताती रही। इसी के चलते 1970-80 के दशक में माओवादी फैलते चले गए। 1990 के दशक की शुरुआत में माओवादियों ने जब छत्तीसगढ़ में बस्तर के साथ ओडिशा, आंध्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर दण्डकारण्य आदिवासी राज्य बनाने के लिए हिंसक गतिविधियां तेज कीं, तब भी कांग्रेस की सरकारें निष्क्रिय बनी रहीं।

इस दौरान सैकड़ों जवान बलिदान हुए और निर्दोष नागरिक मारे गए। आंध्र की वाइएसआर रेड्डी की कांग्रेस सरकार ने तो 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप से समझौता वार्ता तक कर ली थी। हालांकि टीडीपी का रुख खिलाफ रहा। 2003 में माओवादियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर हमला भी किया था।

एक समय माओवादियों ने दक्षिण में अपना जंक्शन बना लिया था, जिसे वे केकेटी जोनल कमेटी कहते थे। केकेटी यानी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। दक्षिण में माओवादियों का कितना असर था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने यहीं आइईडी ब्लास्ट की तकनीक लिट्टे से सीखी थी। माओवादियों ने कांग्रेस को भी घाव दिए। 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की झीरम घाटी में उन्होंने घात लगाकर हमला किया, जिसमें राज्य कांग्रेस का लगभग पूरा नेतृत्व खत्म हो गया। इसके बाद कांग्रेस का रुख थोड़ा बदला, पर 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने माओवादियों के खिलाफ वैसा अभियान नहीं छेड़ा, जैसा आवश्यक था।

जब बीती 31 मार्च माओवाद के खात्मे की डेडलाइन थी, तब तेलगांना की कांग्रेस सरकार ने कहा कि राज्य में किसी माओवादी का एनकाउंटर नहीं होगा। यही वजह रही कि देश के दूसरे हिस्सों में जब माओवादियों का एनकाउंटर हो रहा था, तब तेलंगाना से एक भी बड़े एनकाउंटर की खबर नहीं आई। छत्तीसगढ़ में आपरेशन के दौरान माओवादी भागकर तेलंगाना के जंगलों में शरण ले रहे थे, इसलिए वहां से सिर्फ माओवादियों के सरेंडर की खबरें आईं।

माओवादियों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में अभियान चल रहे थे, लेकिन संघर्ष क्षेत्र बस्तर यानी दण्डकारण्य और अबूझमाड़ का जंगल था। इसी दण्डकारण्य से तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा की सीमा लगती हैं। यहां माओवादियों का जोर था। अबूझमाड़ से गढ़चिरौली-महाराष्ट्र की सीमा लगती है, जिसे पिछले सप्ताह आपरेशन अंतिम प्रहार के बाद आधिकारिक रूप से माओवाद से मुक्त घोषित किया गया। अकेली कांग्रेस ही माओवादियों के प्रति नरम नहीं थी। अनेक ऐसे समूह भी थे, जो उनसे सहानुभूति रखते थे। 2003 में छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की भाजपा सरकार आई तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए नगालैंड आर्म्ड फोर्स की बटालियन बस्तर बुलाई गई। उसने बीजापुर के सलवा जुडूम के साथ मिलकर माओवादियों पर जबरदस्त दबाव बनाया। सलवा जुडूम ग्रामीणों का समूह था, जो माओवादियों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। 2005 से 2007 के बीच नगा बटालियन ने माओवादियों की जड़ें हिला दी थीं।

माओवाद समर्थकों से यह देखा नहीं गया। वामपंथियों ने छत्तीसगढ़ में नगा बटालियन भेजे जाने पर खूब हाय-तौबा मचाई। आखिर 2007 में उसे वापस बुला लिया गया। इससे माओवादियों का हौसला बढ़ा। उन्होंने 2007 में बीजापुर के रानी बोडली गांव में पुलिस कैंप पर हमला कर उसमें आग लगा दी, जिसमें 55 जवान जिंदा जल गए। 2010 में सुकमा के तारमेटला में माओवादियों ने हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान बलिदान हो गए।

2010 ऐसा साल रहा, जिसमें सबसे ज्यादा हिंसा हुई। सलवा जुडूम को भी माओवादी समर्थकों ने चलने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज बी. सुदर्शन रेडडी ने सलवा जुडूम को अवैध ठहरा दिया। गत वर्ष कांग्रेस ने इन्हीं सुदर्शन रेडडी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया। शायद इसी कारण गृहमंत्री अमित शाह ने यह कहा कि आदिवासियों को दशकों तक गुमराह करने और खूनी खेल खेलने वाले लोग अब हार मान चुके हैं, पर वे शांत नहीं बैठेंगे। वे भेष बदलकर फिर से आ सकते हैं। साफ है कि इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि माओवादी फिर सिर न उठाने पाएं।

अभियान

जब सृष्टि बचाने के लिए शिव को लेना पड़ा सबसे भयंकर शरभ रूप

सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं केवल देवताओं की महिमा का वर्णन नहीं करतीं, बल्कि वे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों, धर्म और संतुलन की शिक्षा भी देती हैं। देवताओं की हर लीला के पीछे कोई न कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है। भगवान Shiva और भगवान Vishnu को सनातन परंपरा में एक-दूसरे का पूरक माना गया है। एक सृष्टि के संहारक हैं तो दूसरे पालनकर्ता। दोनों ही एक-दूसरे के परम भक्त और सम्मानकर्ता माने जाते हैं। लेकिन पुराणों में एक ऐसी अद्भुत घटना का वर्णन मिलता है, जब संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए इन दोनों महाशक्तियों को आमने-सामने आना पड़ा। यह घटना इतनी रहस्यमयी और विराट थी कि देवता, ऋषि और समस्त लोक भय से कांप उठे थे। यही वह समय था, जब महादेव को अपने सबसे भयंकर और रहस्यमयी शरभ अवतार में प्रकट होना पड़ा।

यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर दैत्यराज हिरण्यकश्यप का आतंक चरम पर था। हिरण्यकश्यप अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वह लगभग अजेय बन गया था। उसे न दिन में मारा जा सकता था, न रात में। न घर के भीतर, न बाहर। न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। न मनुष्य उसे मार सकता था और न पशु। इस वरदान के अभिमान में वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। जो भी विष्णु का नाम लेता, उसे कठोर दंड दिया जाता।

लेकिन उसी हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। बालक प्रह्लाद हर क्षण नारायण का स्मरण करता था। पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने अपने ही पुत्र को अनेक यातनाएं दीं। कभी विषैले सर्पों के बीच फिंकवाया, कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, तो कभी आग में बैठाया गया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते रहे।

एक दिन क्रोध से भरे हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद से पूछा, "तुम्हारा विष्णु आखिर कहां है?" प्रह्लाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, "पिताश्री, भगवान हर जगह हैं।" यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने महल के एक विशाल स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, "क्या तुम्हारा विष्णु इस स्तंभ में भी है?" प्रह्लाद ने दृढ़ विश्वास से कहा, "हां, भगवान यहां भी हैं।"

इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी एक भयंकर गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उनका यह रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह था। आंखों में अग्नि की ज्वाला, विशाल दांत, नुकीले नाखून और विकराल स्वरूप देखकर देवता भी भयभीत हो उठे। यह ऐसा रूप था, जिसे देखकर स्वयं मृत्यु भी कांप जाए।

भगवान नरसिंह ने संध्या समय हिरण्यकश्यप को राजमहल की चौखट पर पकड़ लिया। उन्होंने न अस्त्र का प्रयोग किया और न शस्त्र का। अपने नुकीले नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान भी बना रहा और अधर्म का अंत भी हो गया।

लेकिन हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप और भी भयानक होता जा रहा था। उनकी गर्जना से दिशाएं कांपने लगीं। पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र उफान मारने लगे और आकाश में भयंकर कंपन होने लगा। देवता समझ गए कि यदि यह क्रोध शांत नहीं हुआ, तो संपूर्ण सृष्टि विनाश की ओर बढ़ जाएगी।

देवताओं ने पहले माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे भगवान नरसिंह को शांत करें, लेकिन माता लक्ष्मी भी उस समय उनके उग्र रूप के पास जाने का साहस नहीं कर सकीं। तब सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि केवल महादेव ही इस प्रचंड शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं।

महादेव ने पहले अपने अंशावतार वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र वही थे, जिन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वे अत्यंत पराक्रमी और उग्र योद्धा माने जाते हैं। उन्होंने भगवान नरसिंह के पास जाकर विनम्रता से निवेदन किया कि वे शांत हो जाएं, क्योंकि अधर्म का अंत हो चुका है। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध उस समय इतना प्रबल था कि उन्होंने वीरभद्र की बात नहीं सुनी।

जब सभी उपाय असफल हो गए, तब स्वयं भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए एक अद्भुत और रहस्यमयी रूप धारण किया। यह रूप था शरभ अवतार। शिव पुराण में शरभ को एक ऐसे दिव्य जीव के रूप में वर्णित किया गया है, जो आधा सिंह, आधा पक्षी और अत्यंत विशालकाय था। उसके आठ पैर थे, विशाल पंख थे और शरीर से अग्नि के समान तेज निकल रहा था। उसके पंजे अत्यंत नुकीले और दांत भयानक थे। यह रूप इतना प्रचंड था कि उसे देखकर बड़े-बड़े देवता भी कांप उठे।

शास्त्रों में वर्णन मिलता है—

"पक्षसिंहमृगाकारं शरभं लोकपावनम्।
अष्टपादं महावीर्यं तीक्ष्णदंष्ट्रं नखाकरम्।।"

अर्थात शरभ रूप पक्षी और सिंह के समान था, आठ पैरों वाला, अत्यंत वीर्यवान, तीक्ष्ण दांतों और नाखूनों से युक्त तथा लोकों को पवित्र करने वाला था।

जब भगवान शिव शरभ रूप में प्रकट हुए, तब आकाश में भयंकर गर्जना गूंज उठी। उनके विशाल पंखों के फड़फड़ाने से दिशाएं कांपने लगीं। उसी समय भगवान नरसिंह भी प्रचंड क्रोध में दहाड़ रहे थे। दोनों महाशक्तियां आमने-सामने थीं। देवता, ऋषि और गंधर्व भय और आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे।

फिर आरंभ हुआ वह अद्भुत युद्ध, जिसकी कल्पना भी कठिन है। नरसिंह भगवान अपनी प्रचंड शक्ति से आक्रमण कर रहे थे, जबकि शरभ रूपी शिव उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। दोनों की गर्जनाओं से ब्रह्मांड कांप रहा था। पर्वत टूटने लगे, समुद्र उग्र हो उठे और दिशाएं अग्नि से भर गईं।

शिव पुराण के अनुसार, शरभ देव ने अंततः अपनी दिव्य शक्ति से भगवान नरसिंह को अपने विशाल पंजों में जकड़ लिया और उन्हें आकाश में ले गए। वहां भगवान नरसिंह ने महादेव के इस विराट और असीम रूप को देखा। धीरे-धीरे उनका क्रोध शांत होने लगा। उन्हें स्मरण हुआ कि वे स्वयं भगवान विष्णु हैं और यह सब लीला सृष्टि की रक्षा के लिए हो रही है।

तब भगवान नरसिंह ने महादेव को प्रणाम किया और कहा—

"त्वं हि ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं हि सर्वं चराचरम्।
क्षमस्व सर्वदेवेश शरभाकृत ईश्वर।।"

अर्थात हे देवों के देव, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं और समस्त चराचर जगत में आप ही व्याप्त हैं। हे शरभ रूपधारी ईश्वर, मुझे क्षमा करें।

इसके बाद भगवान नरसिंह शांत होकर अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए और बैकुंठ धाम चले गए। देवताओं ने राहत की सांस ली। सृष्टि एक बार फिर संतुलित हो गई।

यह कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में कभी वास्तविक विरोध नहीं था। दोनों एक ही परम तत्व के अलग-अलग स्वरूप हैं। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, तब वही परम शक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है।

शरभ अवतार यह भी सिखाता है कि क्रोध, चाहे कितना भी उचित क्यों न हो, यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। भगवान नरसिंह का क्रोध अधर्म के नाश के लिए था, लेकिन जब वही क्रोध सृष्टि के लिए खतरा बनने लगा, तब उसे शांत करना आवश्यक हो गया। महादेव ने यही कार्य किया। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि यहां हर कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का गहन दर्शन प्रस्तुत करती है। भगवान शिव का शरभ अवतार हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप वही है, जो संतुलन बनाए रखे। जब क्रोध और विनाश सीमा पार करने लगें, तब करुणा, विवेक और संतुलन का प्रकट होना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि महादेव को देवों का देव कहा जाता है, क्योंकि वे केवल संहारक नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रक्षक भी हैं।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साइंस सिटी में कॉकलियर इंप्लांट प्रोग्राम के लाभार्थी बच्चों के साथ किया संवाद, मुख्यमंत्री का वात्सल्यभाव देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे

- आवाज मिलने के बाद मुख्यमंत्री के साथ बात करने का अवसर मिलने पर बच्चे हुए खुश
- मुख्यमंत्री बने अभिभावक : कॉकलियर इंप्लांट सहायता प्राप्त करने वाले 20 बच्चों के साथ देखी एक्वाटिक गैलरी
- राज्य सरकार 3.5 लाख रुपए मूल्य का स्पीच प्रोसेसर बिल्कुल मुफ्त देती है, अब मासूमों के जीवन में गूंजेगी आशा भरी आवाज
- बच्चों के अभिभावकों ने राज्य सरकार के कॉकलियर इंप्लांट एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम को जरूरतमंद बच्चों के लिए वरदान बताया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद की साइंस सिटी में राज्य सरकार के कॉकलियर इंप्लांट एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का लाभ उठाने वाले 20 बच्चों के साथ सहज संवाद किया।

वात्सल्य से ओतप्रोत वातावरण में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक आत्मीय बुजुर्ग और अभिभावक के रूप में बच्चों के साथ अपनापन दिखाया। इससे बच्चों के चेहरे मुस्कान से खिल उठे। आवाज मिलने के बाद मुख्यमंत्री के साथ बात करने का अवसर मिलने पर बच्चे खुशी से चहक उठे।

संवाद के दौरान बच्चों के अभिभावकों ने महंगे इंप्लांट बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार तथा इस योजना के सुनियोजित कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) टीम, सरकार के स्वास्थ्य विभाग तथा सोला सिविल सहित अन्य हॉस्पिटलों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बच्चों के साथ साइंस सिटी की प्रसिद्ध 'एक्वाटिक गैलरी' का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने रंगबिरंगी मछलियों और जलचर सृष्टि को हैरानी से देख रहे बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उनके साथ बाल सहज बातें करके वात्सल्यभाव अभिव्यक्त किया। मुख्यमंत्री की इस संवेदनशीलता को देखकर वहां मौजूद बच्चों के माता-पिता और अधिकारियों की आंखें भी हर्ष से भीग उठीं।

मुख्यमंत्री ने सभी अभिभावकों और उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि यदि अभी भी समाज में ऐसे जरूरतमंद बच्चे हों, तो ऐसे बच्चों और उनके परिवारों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए मार्गदर्शन दें।

इस अवसर पर खाद्य एवं औषधि आयुक्त डॉ. रतनकंवर गढ़वी चारण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती विशेष रूप से मौजूद रहे।

बच्चों के अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं :

"विवाह के 13 वर्षों के बाद जन्मे बच्चे के उपचार की आर्थिक चिंता सरकार ने दूर की" – सोनलबेन भावसार

"विवाह के 13 वर्षों के बाद भगवान ने मुझे संतान सुख दिया, लेकिन जब पता चला कि बच्चा बोल-सुन नहीं सकता, तब मैं टूट गई थी। आंगनबाड़ी के दौरे के दौरान आरबीएसके की टीम ने मेरे बच्चे की जांच की और असारवा सिविल हॉस्पिटल में मुफ्त ऑपरेशन कराया। इस सरकारी योजना ने हमारी बहुत बड़ी आर्थिक और मानसिक मदद की है। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने एक अभिभावक बनकर हमारे बच्चों के साथ बातचीत की और बच्चों के साथ घूमें, वह देखकर हमें भरोसा हो गया है कि राज्य के एक बड़े-बुजुर्ग के रूप में मुख्यमंत्री सदैव हमारे साथ खड़े हैं।"

"कॉकलियर इंप्लांट एक बहुत महंगी सर्जरी होने के कारण साधारण परिवारों के लिए यह असंभव होती है, लेकिन यह उम्दा स्कीम लाकर सरकार ने हजारों बच्चों को नवजीवन दिया" – ऋतुल पंचाल

"तीन वर्ष पहले जब यह मालूम हुआ कि हमारी बेटी रूही दोनों कानों से सुन नहीं सकती, तो हम चिंता डूब गए। महंगे उपचार के कारण अनेक हॉस्पिटलों में जाने के बाद हमें सोला सिविल हॉस्पिटल में राज्य सरकार की निःशुल्क कॉकलियर इंप्लांट ऑपरेशन की स्कीम के बारे में पता चला। सोला सिविल के ईएनटी और ऑडियोलॉजी विभाग के उत्कृष्ट मार्गदर्शन के अंतर्गत बेटी सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई और वहां एक वर्ष तक चली स्पीच थेरेपी के कारण आज रूही इतनी अच्छी बातें करती है कि मानों उसे कोई समस्या ही नहीं थी। हमने उसकी स्कूलिंग और सामाजिक मेलमिलाप भी बढ़ा दिया है, ताकि वह बिना किसी हीन भावना के सभी के बीच सहजता से रह सके।"

"कॉकलियर इंप्लांट अत्यंत महंगी सर्जरी होने के कारण साधारण परिवारों के लिए इसका खर्च उठाना असंभव होता है, लेकिन यह उम्दा स्कीम लाकर सरकार ने हजारों बच्चों को नवजीवन दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से आकर इन बच्चों से भेंट की और एक अभिभावक के रूप में उन पर जो स्नेह बरसाया, वह सचमुच ही प्रेरणादायी है। मैं बच्चों को प्रोत्साहित करने और संपूर्ण समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूं।"

"सुनने की समस्या (बहरेपन) से पीड़ित हरेक बच्चे के अभिभावकों को इस स्कीम का लाभ उठाना चाहिए : श्री जैनम शाह"

"जब मेरी बेटी हाश्वी डेढ़ वर्ष की हुई, तब उसके कान की समस्या के बारे में पता चलने पर हमें गहरा धक्का लगा। सोला सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अद्भुत सहयोग से हमने उसका कॉकलियर इंप्लांट ऑपरेशन करवाया। वहां दी गई स्पीच थेरेपी के कारण केवल हमारी बेटी आठ महीने में ही बहुत ही अच्छे से बोलने लगी। एक कान के उपचार के सफल परिणाम से प्रेरित होकर हमने सोला सिविल में ही उसके दूसरे कान का ऑपरेशन भी करवाया। आज ऑपरेशन के डेढ़ वर्ष के बाद साढ़े तीन वर्ष की मेरी बेटी सामान्य बच्चों की तरह एक सामान्य स्कूल में पढ़ती है और एक सामान्य जीवन जी रही है।" मैं उन सभी पैरेन्ट्स से कहना चाहूंगी, जो हिचकिचा रहे हैं, कि बिना किसी चिंता के कॉकलियर इंप्लांट स्कीम का लाभ उठाएं, यह सरकारी योजना ऐसे बच्चों के लिए एक वरदान की तरह है।

क्या है कॉकलियर इंप्लांट एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम?

- गुजरात सरकार द्वारा 6 वर्ष तक की उम्र के संपूर्ण बहरेपन से पीड़ित मासूम बच्चों का बिल्कुल मुफ्त कॉकलियर इंप्लांट करवाने का प्रोग्राम
- यह उम्दा सेवा यज्ञ वर्ष 2014 से 'शाला आरोग्य कार्यक्रम' के अंतर्गत शुरू किया गया है, जिसके तहत अब तक 3500 से अधिक बच्चों का कॉकलियर इंप्लांट हो चुका है।
- राज्य के बच्चों को स्थानीय स्तर पर ही यह अत्याधुनिक उपचार सुलभ कराने के लिए गुजरात के 10 प्रतिष्ठित हॉस्पिटलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- वर्ष 2024 में राज्य सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत जिन बच्चों के एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर खराब हो गए हैं, टूट गए हैं या गुम हो गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्पीच प्रोसेसर को एक बार बिल्कुल मुफ्त रिप्लेस कर दिया जाएगा।
- अब तक 401 बच्चों के एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर रिप्लेस किए जा चुके हैं।
- बाजार में एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर की अनुमानित कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए होती है, जिसे वहन करना मध्यम या गरीब वर्ग के परिवारों के लिए संभव नहीं होता।
- इस पूरे प्रोग्राम को और मजबूत और परिणाम-उन्मुख बनाने के लिए विशेषज्ञ ईएनटी सर्जन, ऑडियोलॉजिस्ट (जो ऑपरेशन से पहले जांच और ऑपरेशन के बाद मैपिंग का काम करते हैं) तथा स्पीच लैंग्वेज थेरापिस्ट (जो बच्चों को सुनना और बोलना सिखाते हैं) दिन-रात सेवारत रहते हैं

कॉकलियर इंप्लांट डिवाइस के बारे में

- कॉकलियर इंप्लांट ऑपरेशन के मुख्य दो हिस्से होते हैं- इंटरनल इंप्लांट और एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर
- प्रोसेसर बाहर की आवाज को अंदर के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से (जो कान में प्रत्यारोपित किया गया हो) तक पहुंचाता है, जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आंतरिक कान (कॉक्लिया) से लेकर दिमाग के केंद्र तक पहुंचाया जाता है।
- चूंकि एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, इसलिए समय के साथ रोजाना के घिसाव, नमी, बैटरी की कम होती कार्यक्षमता, केबल को होने वाले नुकसान या तार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण खराब होने की संभावना रहती है।
- स्पीच प्रोसेसर का जीवनकाल लगभग 10 वर्ष होता है, समय के साथ इसे अपग्रेड करना या बदलना पड़ता है।

डिजिटल जनगणना से पहले सूरत प्रशासन पर बढ़ा दबाव, कर्मचारियों की कमी और ड्यूटी से बचने की कोशिशों ने बढ़ाई चिंता

सूरत। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक और डेटा आधारित प्रक्रिया मानी जा रही Census of India 2027 की डिजिटल शुरुआत से पहले गुजरात का औद्योगिक शहर सूरत बड़ी प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। 1 जून से शुरू होने वाली 50 दिन की व्यापक जनगणना प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हैं, लेकिन कर्मचारियों की भारी कमी, ड्यूटी से छूट की बढ़ती मांग और कई कर्मचारियों द्वारा जनगणना कार्य से बचने की कोशिशों ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। तेजी से बढ़ती आबादी वाले इस शहर में पहली बार बड़े पैमाने पर पूरी तरह डिजिटल माध्यम से जनगणना कराना प्रशासन के लिए किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं माना जा रहा।

सूत्रों के अनुसार सूरत में जनगणना कार्य के लिए लगभग 15,800 कर्मचारियों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में करीब 2,300 कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पहले से नियुक्त और प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों में से भी बड़ी संख्या अब ड्यूटी से छूट मांग रही है। बताया जा रहा है कि 900 से अधिक कर्मचारियों ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए जनगणना कार्य से हटाए जाने के लिए आवेदन दिए हैं। इनमें से लगभग 190 कर्मचारियों ने तो किसी भी परिस्थिति में फील्ड ड्यूटी नहीं करने की इच्छा जताई है। अधिकारियों का कहना है कि कई लोग छोटे-बड़े व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

सूरत प्रशासन के लिए यह स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है और अनुमान है कि अब यह संख्या 85 लाख के करीब पहुंच चुकी है। शहर में लगभग 18 लाख आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का घर-घर जाकर डिजिटल सर्वे किया जाना है। इस बार जनगणना पूरी तरह तकनीक आधारित होगी, जिसमें कर्मचारियों को मोबाइल उपकरणों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा एकत्र करना होगा। प्रशासन का मानना है कि इतनी बड़ी आबादी और विस्तृत शहरी क्षेत्र में डिजिटल जनगणना को सफलतापूर्वक पूरा करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है।

शुरुआत में प्रशासन ने करीब 10 हजार कर्मचारियों को ड्यूटी आदेश जारी किए थे, लेकिन शहर के विस्तार और जनसंख्या घनत्व को देखते हुए यह संख्या बढ़ाकर 14,800 कर दी गई। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत रिजर्व स्टाफ भी तैयार रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत तैनात किया जा सके। अब तक लगभग 12 हजार एन्यूमरेटर और 2 हजार सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके बावजूद आवश्यक संख्या पूरी नहीं हो पाई है। अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न सरकारी विभागों से अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की गई है और कमी को पूरा करने के लिए नई नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन को मिली शिकायतों के अनुसार कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी भी जनगणना ड्यूटी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का अभियान है, इसलिए सभी विभागों के कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि बिना उचित और वैध कारण के ड्यूटी से बचने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

900 से अधिक कर्मचारियों द्वारा दी गई छूट संबंधी अर्जियों में स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक परिस्थितियां, मानसिक दबाव और अन्य व्यक्तिगत कारणों का उल्लेख किया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि केवल गंभीर और प्रमाणित कारणों के आधार पर ही छूट दी जाएगी। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सामान्य बहानों के आधार पर ड्यूटी से मुक्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कई मामलों में कर्मचारियों से अतिरिक्त दस्तावेज और मेडिकल प्रमाणपत्र भी मांगे गए हैं।

इस बीच एक अन्य विवाद तब सामने आया जब जल्दबाजी में जारी ड्यूटी आदेशों में दिव्यांग और गर्भवती कर्मचारियों को भी फील्ड ड्यूटी सौंप दी गई। इस पर कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों ने आपत्ति जताई। शिकायतों के बाद प्रशासन ने मामले की समीक्षा की और पाया कि कुल 335 दिव्यांग तथा गर्भवती कर्मचारियों को जनगणना के फील्ड कार्य में लगाया गया था। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत उनके आदेश रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की और उनकी जगह नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। इस फैसले के बाद संबंधित कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार की डिजिटल जनगणना केवल जनसंख्या गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की शहरी योजना, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा और सरकारी योजनाओं की दिशा तय करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। खासतौर पर सूरत जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों के लिए सटीक आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

वकीलों की सुरक्षा को लेकर सूरत से उठी मजबूत आवाज, महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र की मांग तेज

सूरत। देशभर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा, बढ़ते हमलों और महिला वकीलों के साथ कथित उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर अब कानूनी समुदाय के भीतर चिंता और मुखर होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में Preeti Jignesh Joshi ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने तथा महिला वकीलों की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी और शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की मांग उठाई है। उनके इस कदम को देशभर के अधिवक्ताओं, विशेष रूप से महिला वकीलों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने की पहल माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार 20 मई 2026 को एडवोकेट प्रीति जिग्नेश जोशी और Deepika Chavda ने दिल्ली स्थित Bar Council of India कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की और अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान दोनों अधिवक्ताओं ने लिखित प्रस्तुति के माध्यम से देशभर में वकीलों के सामने बढ़ रही चुनौतियों और असुरक्षा के माहौल को गंभीर विषय बताया।

एडवोकेट प्रीति जोशी ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अधिवक्ताओं पर हमले, झूठे मुकदमे, दबाव, धमकी और उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में वकीलों को केवल अपने मुवक्किलों का पक्ष मजबूती से रखने के कारण निशाना बनाया जाता है। इससे न केवल अधिवक्ताओं में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं और यदि वही स्वयं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता भी प्रभावित होगी। उनका कहना था कि कई बार वकीलों को दबाव में लाने, डराने या कानूनी लड़ाई से पीछे हटाने के लिए झूठे मामलों में फंसाने और धमकाने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं को कानूनी और संस्थागत सुरक्षा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

एडवोकेट प्रीति जोशी ने मांग की कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक विशेष राष्ट्रीय समिति गठित करे, जो पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करे। उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके सख्त और व्यावहारिक क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मजबूत प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट और प्रभावी नीति लागू की जा सके।

महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई महिला वकीलों को कोर्ट परिसरों, बार रूम और निजी चैंबरों में मानसिक, सामाजिक और कभी-कभी शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कई घटनाएं सामने नहीं आ पातीं क्योंकि पीड़ित महिलाएं पेशेवर दबाव और सामाजिक कारणों से शिकायत दर्ज कराने से बचती हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए उन्होंने प्रत्येक बार एसोसिएशन स्तर पर अधिकृत और सक्रिय शिकायत निवारण समिति यानी ग्रिवांस सेल गठित करने की मांग की।

उनका कहना था कि ऐसी समितियां केवल औपचारिक न हों, बल्कि उन्हें वास्तविक अधिकार और जवाबदेही दी जाए, ताकि महिला अधिवक्ता बिना भय के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि महिला वकीलों की सुरक्षा केवल व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की गरिमा और पेशेवर वातावरण से जुड़ा प्रश्न है।

इस दौरान एडवोकेट प्रीति जोशी और एडवोकेट दीपिका चावड़ा ने Manan Kumar Mishra को लिखित रजुआत भी सौंपी। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी विधिक संस्था है और अधिवक्ताओं के अधिकारों तथा हितों की रक्षा में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। दोनों अधिवक्ताओं ने उम्मीद जताई कि बीसीआई इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय करेगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में अधिवक्ताओं पर हमले और उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं। कई राज्यों में वकीलों ने सुरक्षा कानून की मांग को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन भी किए हैं। अधिवक्ता संगठनों का कहना है कि डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों की तरह वकीलों के लिए भी विशेष सुरक्षा कानून की आवश्यकता है, ताकि वे बिना किसी डर के अपना पेशेवर दायित्व निभा सकें। महिला अधिवक्ताओं के संदर्भ में यह मुद्दा और भी संवेदनशील माना जा रहा है। न्यायालय परिसरों में सुरक्षित कार्य वातावरण, लैंगिक सम्मान और उत्पीड़न के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग लंबे समय से उठती रही है। अब सूरत से उठी यह आवाज राष्ट्रीय स्तर पर बहस को नई दिशा दे सकती है।

स्वच्छ हवा से 'ब्रांड सूरत' तक: ब्रीदिंग सिटीज़ डायलॉग में पर्यावरण, विकास और भविष्य पर मंथन

सूरत। तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक और व्यावसायिक शहर सूरत में अब विकास के साथ पर्यावरण संतुलन और स्वच्छ हवा को लेकर भी गंभीर विमर्श शुरू हो गया है। इसी दिशा में The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Indian Institute of Architects के सूरत रीजनल चैप्टर और Indian Institute of Interior Designers के संयुक्त तत्वावधान में "ब्रीदिंग सिटीज़ः ए मल्टी-स्टेकहोल्डर डायलॉग ऑन एयर पॉल्यूशन" विषय पर एक हाई-लेवल पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया। सरसाना स्थित उषाकांत मारफतिया हॉल में हुए इस कार्यक्रम में शहर के उद्योगपतियों, पर्यावरण विशेषज्ञों, डॉक्टरों, आर्किटेक्ट्स, शहरी योजनाकारों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर सूरत के भविष्य, स्वच्छ हवा और "ब्रांड सूरत" की नई पहचान पर गंभीर चर्चा की।

कार्यक्रम के दौरान यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि सूरत अब केवल व्यापार और उद्योग का केंद्र नहीं रहना चाहता, बल्कि वह खुद को एक स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वक्ताओं ने माना कि तेजी से बढ़ती आबादी, औद्योगिक विस्तार, वाहनों की संख्या और शहरीकरण के दबाव के बीच स्वच्छ हवा और हरित विकास को प्राथमिकता देना समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चैंबर अध्यक्ष Nikhil Madrasi ने कहा कि सूरत ने वर्ष 1994 के प्लेग संकट के बाद खुद को पूरी तरह बदलते हुए देश के सबसे स्वच्छ शहरों में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने कहा कि अब शहर को एक नई पर्यावरणीय चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और केवल चर्चा से समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदूषण के खिलाफ ठोस, सामूहिक और दीर्घकालिक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने मशहूर पंक्तियों "सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है..." का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आज के शहरी प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है।

मुख्य अतिथि और M. Nagarajan ने कार्यक्रम में सूरत नगर निगम द्वारा किए जा रहे पर्यावरणीय प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मिले 322 करोड़ रुपये के फंड का नगर निगम ने शत-प्रतिशत उपयोग किया है और इसके परिणामस्वरूप शहर में PM10 प्रदूषण स्तर में 33.84 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। उन्होंने इसे प्रशासन, उद्योग और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सोलर पैनल, ग्रीन कवर, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सार्वजनिक पार्कों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मेट्रो उपयोग को बढ़ावा देने, साइकिल ट्रैक और सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम को फिर से सक्रिय करने की योजना पर भी तेजी से काम किया जाएगा। उनका मानना था कि यदि लोग निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का अधिक उपयोग करें, तो शहर में वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कार्यक्रम में एलर्जी और अस्थमा विशेषज्ञ Sameer Gami ने इनडोर एयर पॉल्यूशन यानी घरों के भीतर बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवनशैली में बंद एसी युक्त घरों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे घरों के अंदर प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक रूप से बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत वडोदरा में रोजगार मेला का आयोजन, 80 नवनियुक्त युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन पहल के अंतर्गत देश भर में आयोजित 19वें रोजगार मेले का उद्घाटन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को सम्बोधित भी किया। यह रोजगार मेला देश भर के 47 विभिन्न स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया जिसके तहत 51000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वडोदरा में प्रतापनगर डिविजनल रेलवे ऑडिटोरियम में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे एवं माननीय विधायक श्री केयुरभाई नारायणदास रोकडिया की गरिमामय उपस्थिति रही। जिसके अंतर्गत रेलवे, बैंक एवं डाक विभागों के कुल 80 पदों पर युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गये।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए नियुक्त लोगों को संबोधित करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी सबसे पहले और सबसे अहम रूप से लोगों के जीवन को आसान बनाने का एक माध्यम है। उन्होंने हर युवा 'कर्मयोगी' से आह्वान किया कि वे अपनी पद को एक जीवंत जिम्मेदारी के रूप में देखें, भारत के लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को समझें और उसी के अनुसार अपने काम को ढालें। माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपना पूरा विश्वास दोहराते हुए कहा कि ये नए नियुक्त कर्मचारी भारत की विकास यात्रा को एक नई गति प्रदान करेंगे, और उनके काम तथा निर्णयों के माध्यम से 'विकसित भारत' का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को उनके भविष्य के सफर के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री ने नव नियुक्त युवाओं को ईमानदारी, समर्पण एवं पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं से अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी लगन एवं सत्यनिष्ठा से करने का आह्वान किया।

वडोदरा में आयोजित समारोह में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने उपस्थित सभी जनों को संबोधित किया। इस दौरान माननीय विधायक श्री केयुरभाई नारायणदास रोकडिया तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में वडोदरा मंडल के शाखा अधिकारी एवं रेलकर्मी भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया गया है। अब तक बारह लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि यह केवल नौकरी नहीं, बल्कि देश सेवा का अवसर है। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप सभी युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय भी विकसित भारत के निर्माण में निरंतर योगदान दे रहा है तथा "हर घर जल" अभियान के अंतर्गत करोड़ों घरों तक पेयजल पहुंचाने का कार्य किया गया है।

कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के जोनल हेड श्री विनय कुमार राठी तथा डाक विभाग के उप अधीक्षक श्री टी. एन. मलिक भी माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने भी युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किये।

रोजगार मेला भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से देशभर के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे है।

कार्यक्रम के अंत में वडोदरा मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। 19वें रोजगार मेले में पश्चिम रेलवे के अंतर्गत वडोदरा मंडल के अलावा अहमदाबाद एवं राजकोट मंडल में भी नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

कार्यक्रम के सफल आयोजन पर वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार तथा इस महत्वपूर्ण आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।

जनगणना-2027 में डिजिटल भागीदारी की अपील, राजकोट पुलिस कमिश्नर ने पूरी की ऑनलाइन स्व-गणना

राजकोट। देशभर में शुरू हुई Census of India 2027 की तैयारियों के बीच गुजरात में भी ऑनलाइन 'स्व-गणना' अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में राजकोट शहर के पुलिस कमिश्नर Brajesh Kumar Jha ने स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी स्व-गणना प्रक्रिया पूरी कर नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से शुरू की गई यह व्यवस्था लोगों के लिए बेहद आसान, तेज और सुविधाजनक है तथा इससे जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार झा ने कहा कि जनगणना केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की विकास योजनाओं और नीतियों की आधारशिला होती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे थोड़ा समय निकालकर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सहयोग करें और ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा का लाभ उठाएं। उनके अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक अब अपने घर बैठे मोबाइल फोन या कंप्यूटर से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं, जिससे समय की बचत के साथ प्रक्रिया अधिक सरल हो गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है। जनगणना-2027 की ऑनलाइन स्व-गणना प्रक्रिया इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे लोगों को सरकारी कर्मचारियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का उपयोग करेंगे और जनगणना को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।

इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने साइबर सुरक्षा को लेकर भी लोगों को विशेष रूप से सतर्क किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति फोन कॉल या किसी अन्य माध्यम से स्व-गणना के नाम पर ओटीपी मांगता है, तो किसी भी परिस्थिति में ओटीपी साझा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी अक्सर सरकारी प्रक्रियाओं के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं और ऐसी स्थिति में सावधानी बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या संदेश से सतर्क रहें।

गौरतलब है कि भारत सरकार के Ministry of Home Affairs द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत ऑनलाइन घरों की गणना और पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in उपलब्ध कराया गया है, जहां नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह स्व-गणना सुविधा फिलहाल 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करें, ताकि आगामी घर-घर जनगणना प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक नागरिक को 11 अंकों का एक यूनिक कोड प्राप्त होगा। यह कोड आगामी 1 जून से शुरू होने वाली घर-घर जनगणना के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब गणना अधिकारी सत्यापन के लिए घर पहुंचेगा, तब नागरिकों को यही यूनिक कोड दिखाना होगा। इससे पहले से दर्ज जानकारी का मिलान और सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल स्व-गणना की शुरुआत भारत की जनगणना प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। अब तक जनगणना पूरी तरह अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर की जाती रही है, लेकिन इस बार तकनीक के उपयोग से नागरिकों को स्वयं भागीदारी का अवसर दिया गया है। इससे न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आंकड़ों को तेजी से संकलित और विश्लेषित करने में भी मदद मिलेगी।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जनगणना के आंकड़े देश की आर्थिक, सामाजिक और विकास योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, परिवहन और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में जनगणना के आंकड़ों का व्यापक उपयोग किया जाता है।

ग्रीन टेक्नोलॉजी से गुजरात की सड़कों का कायापलट : विभिन्न जिलों की 20 सड़कों पर 1147 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगा काम

▶▶ पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक टेक्नोलॉजी से खर्च में कमी आएगी और सड़कों की उम्र भी लंबी होगी

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की क्रांति राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में और मजबूत हुई

गांधीनगर : गुजरात की सड़कों को आधुनिक बनाकर पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ विकास की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'स्पीड और स्केल' के विजन के अनुसार भारत के सड़क नेटवर्क के विकास की गति और उसके स्केल में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस विजन के अनुरूप राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में इस वर्ष के बजट में 1147 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण में क्लाइमेट रेजिलिएंट और नई टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रावधान किया गया है।

इसके अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों में 20 सड़कों पर इस ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से काम शुरू होने जा रहा है। इस प्रक्रिया में मौजूदा सड़कों के पुराने मटीरियल का दोबारा इस्तेमाल करके सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे न केवल लागत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

राज्य की इन सड़कों पर ग्रीन टेक्नोलॉजी के अनुसार होगा काम

लणवा-मणुंद-संडेर-बालीसाणा रोड (पाटण), राधनपुर-मशाली-माधापुरा रोड (पाटण), भीड़िया सोमनाथ रोड (गिर सोमनाथ), संतरामपुर-झालोद रोड (महिसागर), दयादरा-नबीपुर-झनोर रोड (भरूच), इलाव-कोसंबा रोड (भरूच), मोरबी-नानी वावड़ी-बगथळा रोड (मोरबी), सुरेन्द्रनगर बाईपास रोड (सुरेन्द्रनगर), डिंडोली-करड़वा-इकलेरा रोड (सूरत), मांगलेज-नारेश्वर रोड (वडोदरा), कोसिंद्रा-भाखा रोड (छोटा उदेपुर), करजण-आमोद रोड (वडोदरा), इसरवाड़ा-उंदेल रोड (आणंद), वालम-कड़ी रोड (मेहसाणा), पेपळु-कापरा रोड (मेहसाणा), लुणी-गुंदाला-पत्री-टप्पर-बाबिया रोड (कच्छ), वड़ताल-जोळ-बाकरोल रोड (आणंद), तळाजा-गोपनाथ रोड (भावनगर), कालावड़-जामवंथली-फल्ला रोड (जामनगर) और कोठारा एप्रोच रोड (नर्मदा)।

इन सड़कों पर अलग-अलग सड़कों की जरूरत के मुताबिक सड़क चौड़ीकरण का काम, आरसीसी गटरलाइन, रीसर्फेसिंग, प्रोटेक्शन वर्क, फोरलेन, मिट्टी काम, रंबल स्ट्रिप, रोड फर्नीचर, साइड शोल्डर, व्हाइट टॉपिंग और ग्लास ग्रिड जैसे कार्य किए जाएंगे। इन सड़कों पर पर्यावरण के अनुकूल (क्लाइमेट रेजिलिएंट) और नई टेक्नोलॉजी के अनुसार काम किया जाएगा।

कैसे काम करती है ग्रीन टेक्नोलॉजी

?

ग्रीन टेक्नोलॉजी के काम में मौजूदा सड़क की पुरानी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें सड़क को उखाड़कर वहां चूना बिछाया जाता है। इस सामग्री को पीसकर (चूरा) करके उस पर रोलर का इस्तेमाल करके स्थिर किया जाता है। उसके बाद, उखाड़ी गई पुरानी सड़क की सामग्री को इस सतह पर बिछाकर ड्राई रोलिंग किया जाता है। उसके बाद, उस पर सीमेंट स्प्रेडर मशीन से सीमेंट बिछाकर उस पर केमिकल युक्त सीमेंट का स्टेबिलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद, पैड फुट रोलर, ग्रेडर और न्यूमेटिक टायर रोलर से उसका लेवलिंग ओर कॉम्पेक्शन किया जाता है। इस कार्य के सात दिनों के बाद नॉन वूवन मटीरियल-स्ट्रेस एब्जॉर्बिंग मेंब्रेन (एसएएमआई) बिछाकर उस पर डामर की परत लगाई जाती है। एसएएमआई एक प्रकार की हाई-टेक फाइबर शीट होती है, जिसे डामर बिछाने से पहले लगाया जाता है। यह दरारों को सतह तक पहुंचने से रोकती है, गाड़ियों के दबाव को अवशोषित करने में सहायक होती है और सड़क की उम्र बढ़ाती है।

ग्रीन टेक्नोलॉजी के लाभ

इस टेक्नोलॉजी में पुराने पेवमेंट की मिट्टी तथा मेटल जैसे मटीरियल का दोबारा उपयोग किया जाता है। इससे लागत कम होती है और सड़क का बेस मजबूत होता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सड़क को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए आवश्यक बेस को बेहतर बनाया जाता है, जिससे सड़क की मजबूती बढ़ती है और उस पर बार-बार मरम्मत कार्य करने की जरूरत भी कम पड़ती है। इस कार्य से कार्बन उत्सर्जन में कमी होने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों की बचत भी होती है।

बल्क ड्रग पार्क को जोड़ने वाली सड़क से औद्योगिक क्षेत्र को फायदा

भरूच में जंबूसर-टंकाली-देवला रोड पर 50 करोड़ रुपए के खर्च से ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रिकंस्ट्रक्शन की मंजूरी दी गई है। यह सड़क जंबूसर के निकट फार्मास्युटिकल बल्क ड्रग पार्क को जोड़ती है, साथ ही ओएनजीसी प्लांट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इसके अलावा, यह सड़क देवला के पास नमक की खेती वाले क्षेत्र को भी संपर्क प्रदान करती है। यहां समुद्री तट के पास झिंगा पालन के तालाबों के लिए भी यह सड़क जंबूसर को वडोदरा जिले से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण राज्य हाईवे है। इस कारण यह वडोदरा से रेलवे, एयरपोर्ट और एक्सप्रेस-वे के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों के साथ सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस प्रकार, विभिन्न इकाइयों को सीधी कनेक्टिविटी मिलने से औद्योगिक दृष्टि से इस सड़क से बहुत लाभ होगा।

सड़क निर्माण की नई टेक्नोलॉजी और डिजाइनों की संक्षिप्त जानकारी

▶▶ वेस्ट प्लास्टिक रोड : प्लास्टिक को डामर के साथ मिक्स किया जाता है।

▶▶ व्हाइट टॉपिंग : पुराने डामर पर कंक्रीट बिछाया जाता है।

▶▶ जियोग्रिड और ग्लास ग्रिड : पॉलिमर की जाली (ग्रिड) और फाइबर ग्लास की ग्रिड बिछाकर मजबूत सड़क बनाई जाती है। जियोग्रिड नरम मिट्टी में ज्यादा मददगार होता है। सड़क के भार को वितरित करने में मदद करता है। ग्लास ग्रिड डामर की परत के बीच बिछाया जाता है, जो सड़क की उम्र बढ़ाता है और मजबूती देता है।

▶▶ कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट : बिना गर्म किए डामर मिक्स का उपयोग मानसून के समय में भी काम करने में उपयोगी साबित होता है।

▶▶ सीमेंट स्टेबिलाइजेशन : सड़क के बेस या मिट्टी में सीमेंट मिलाकर एक मजबूत परत बनाई जाती है।

▶▶ फ्लाई ऐश : थर्मल पावर प्लांट के कोयले के पाउडर का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है।

▶▶ इंटरलॉकिंग पेवर्स : छोटे कंक्रीट ब्लॉक्स को एक-दूसरे के साथ लॉक करके बिछाया जाता है।

▶▶ पैनल्ड कंक्रीट : एक साथ लंबी सड़क बनाने के बजाय कंक्रीट के अलग-अलग स्लैब बिछाकर सड़क का निर्माण।

▶▶ पर्पेच्युअल पेवमेंट : बहुत सारी परतों के साथ एक मजबूत सड़क का निर्माण। इस सड़क का मरम्मत खर्च कम रहता है और सड़क लंबे समय तक चलती है।

भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत: भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर निःशुल्क छाछ का वितरण

भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान के मद्देनज़र यात्रियों को राहत प्रदान करने हेतु पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जनहित में विशेष पहल की गई है। इस क्रम में दिनांक 23 मई, 2026 (शनिवार) को भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए निःशुल्क छाछ वितरण की व्यवस्था की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मुख्य प्रवेश द्वार और प्लेटफॉर्म क्षेत्र में यात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों को छाछ उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें भीषण गर्मी से काफी राहत मिली।

निःशुल्क छाछ वितरण सेवा में भावनगर की सामाजिक संस्था "फैंटास्टिक-14" का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। स्टेशन पर इन व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने में भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों, टिकट चेकिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा वितरण कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न किया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा ने कहा, "भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावनगर मंडल द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस प्रकार की जनहितकारी गतिविधियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यह पहल हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं यात्री-हित के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।"

भावनगर मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं मानवीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती रहें। भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार की राहत सेवाएँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

दुनिया का सबसे महंगा दूध! चूहे के दूध की कीमत लाखों में है और इसका इस्तेमाल चिकित्सा अनुसंधान में किया जाता है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले दूध की कीमत आमतौर पर 60 से 100 रुपये प्रति लीटर होती है। लेकिन क्या आपने कभी लाखों रुपये में बिकने वाले दूध के बारे में सुना है? चूहे का दूध दुनिया का सबसे महंगा दूध माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20 से 23 लाख रुपये प्रति लीटर तक हो सकती है।

चूहे का दूध इतना महंगा होने का एक कारण यह है कि एक लीटर दूध इकट्ठा करने के लिए हजारों चूहों की जरूरत पड़ती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, लगभग 40,000 चूहों से दूध इकट्ठा करने के बाद भी मुश्किल से एक लीटर दूध ही प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया न केवल श्रमसाध्य है, बल्कि तकनीकी रूप से भी बेहद जटिल है। इस दूध का उपयोग न केवल सामान्य भोजन और पेय पदार्थों के लिए किया जाता है, बल्कि चिकित्सा अनुसंधान में भी होता है। चूहों के दूध की मांग विशेष रूप से दवाओं और टीकों के परीक्षण के लिए है। वैज्ञानिकों के अनुसार, चूहे के दूध में मौजूद प्रोटीन और अन्य तत्वों में मानव डीएनए से कुछ समानताएं होने के कारण यह अनुसंधान में बहुत उपयोगी साबित होता है। देखिए, यह एक दिलचस्प कहानी है।

सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ के नए पदाधिकारियों के लिए एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत..

सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों - अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव, उपाध्यक्ष किरीटभाई वाघेला, महासचिव मोहम्मद इकबाल शेख और मंत्री हरीशभाई राठौड़ - का अभिनंदन समारोह 23 मई, 2026 को गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष के आवास पर कर्मचारी संघ के नेताओं, संघ नेता जयंतीभाई वाघेला द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत सोलंकी ने स्वागत भाषण देकर किया। समारोह में उपस्थित संघ नेताओं और पदाधिकारियों में सर्वश्री मोहनभाई राठौड़, अर्जुन वीरस, कनैय्याभाई सोलंकी, रणजीत पटेल, सुभाष सोलंकी, सुरेश सोलंकी, अतुल सोलंकी, महेंद्र जाधव, नीलांग देसाई, जयसिंहभाई गोहिल, प्रवीण सोलंकी, नितिन सोलंकी आदि शामिल थे। उन्होंने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और उन्हें पुष्प अर्पित कर सम्मानित किया। अध्यक्ष की कुर्सी से जयंतीभाई वाघेला ने सभी यूनियनों से एकजुट होकर महामंडल द्वारा आयोजित आंदोलन कार्यक्रमों में शामिल होने का आह्वान किया। महामंडल अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव ने सभी नेताओं और कर्मचारियों से आज की स्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अनुरोध किया। महासचिव मोहम्मद इकबाल शेख ने यूनियनों की 70 वर्षों की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में गुजरात प्रदेश महानगरपालिका कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष कनैयालाल सोलंकी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

कच्छ में रेलवे विकास को मिलेगी नई गति : पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे का कच्छ दौरा

मुंद्रा पोर्ट से लेकर भुज-नलिया रेलखंड तक विकास परियोजनाओं एवं रेलवे अधोसंरचना का किया निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे ने 22 एवं 23 मई, 2026 को कच्छ क्षेत्र का व्यापक दौरा कर रेलवे परियोजनाओं, अधोसंरचना विकास कार्यों तथा भावी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गांधीधाम–मुंद्रा पोर्ट सेक्शन का निरीक्षण यान से विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया तथा भुज-नलिया-वायोर रेलखंड का गहन निरीक्षण भी किया।

22 मई, 2026 को गांधीधाम से मुंद्रा पोर्ट के बीच किए गए निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने गांधीधाम क्षेत्र में चल रहे विभिन्न रेलवे प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे अहमदाबाद के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) प्रदीप गुप्ता, अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश सहित निर्माण एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुंद्रा पोर्ट दौरे के दौरान महाप्रबंधक ने APSEZ के CEO सुजल शाह के साथ ट्रेन कनेक्टिविटी एवं ट्रेन संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पोर्ट के मॉडल रूम में APSEZ के COO मनोज कतर द्वारा मुंद्रा पोर्ट के विकास एवं पिछले 13 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। इस दौरान रो-रो टर्मिनल का अवलोकन भी बोट के माध्यम से किया गया। महाप्रबंधक ने Adani Ports and Special Economic Zone के अधिकारियों के साथ बैठक कर रेलवे एवं पोर्ट के बीच समन्वय तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

भुज-दिल्ली नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के शुभारंभ अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक श्री पाण्डेय ने कहा कि कच्छ में रेलवे के आधारभूत ढांचे के विकास एवं नई रेलवे सुविधाओं के लिए आने वाले वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि भुज-आदिपुर के बीच डबल रेलवे ट्रैक के लिए सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे भविष्य में परिवहन अधिक तेज एवं सुगम होगा।

महाप्रबंधक श्री पाण्डेय एवं मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने जानकारी दी कि भुज रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। स्टेशन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है तथा कार्य पूर्ण होने के बाद इसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा भचाऊ एवं गांधीधाम रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि भुज स्टेशन के नवनिर्माण के बाद रेलवे सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा तथा कच्छ में जहां व्यापार एवं यातायात की आवश्यकता होगी, वहां नई रेलवे परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी।

भुज-दिल्ली रेल सेवा के शुभारंभ के बाद गांधीधाम में उद्योगपतियों एवं व्यापारिक संगठनों के साथ आयोजित बैठक में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्योग जगत की समस्याएं एवं सुझाव सुने। गांधीधाम चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने कहा कि रेलवे की कार्यशैली एवं सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों एवं माल परिवहन के लिए कई विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद रेलवे के माध्यम से परिवहन बढ़ना देशहित में है। कच्छ के व्यापार एवं उद्योग जगत से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु रेलवे द्वारा जोनल एवं रेलवे बोर्ड स्तर पर सक्रिय प्रयास किए जाएंगे।

अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने कहा कि रेलवे का प्रयास है कि उद्योग जगत एवं यात्रियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि रेलवे उद्योग जगत की समस्याओं को गंभीरता से समझती है तथा नीति से जुड़े विषयों के समाधान हेतु आवश्यक परिवर्तन करने का प्रयास भी किया जाएगा।

बैठक के दौरान चेंबर ऑफ कच्छ के प्रतिनिधियों ने मांडवी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने, पूर्व स्वीकृत रेलवे कोच फैक्ट्री को प्रारंभ करने, नमो भारत ट्रेन को डबल रैक के साथ चलाने तथा भुज-हरिद्वार, भुज-वाराणसी, भुज-भागलपुर एवं भुज-अमृतसर जैसी लंबित ट्रेन मांगों को प्राथमिकता देने सहित विभिन्न विषय उठाए। साथ ही डीपी वर्ल्ड द्वारा जून 2027 तक प्रस्तावित मेगा कंटेनर टर्मिनल एवं बढ़ते माल परिवहन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त रेलवे सुविधाओं के विकास का अनुरोध भी किया गया।

23 मई, 2026 को महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने भुज-नलिया-वायोर रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भुज-नलिया सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। साथ ही नलिया स्टेशन एवं नलिया-वायोर नई रेलवे लाइन परियोजना के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में आयोजित 19वें रोजगार मेले के तहत 51 हजार से अधिक युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र

अहमदाबाद में आयोजित रोजगार मेले में 115 नव अभ्यर्थियों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मई, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले के अंतर्गत देशभर में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने नव नियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अब पारदर्शिता आई है तथा सभी चयन मेरिट के आधार पर किए जा रहे हैं। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज एवं सुगम हुई है।

19वां रोजगार मेला देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न 19 विभागों से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की गईं। रोजगार मेला अभियान प्रारंभ होने के बाद से अब तक देशभर में आयोजित विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12.50 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

अहमदाबाद में आयोजित रोजगार मेले में मुख्य अतिथि, माननीया युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री, भारत सरकार, श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने अपने संबोधन में कहा कि आज गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व 18 रोजगार मेलों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से लगभग 12 लाख युवाओं को केंद्र सरकार द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। आज भी इस रोजगार मेले के माध्यम से लगभग 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और विकास मॉडल के लिए पूरे देश एवं विश्व में जाना जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा से यह रही है कि देश का प्रत्येक युवा आगे बढ़े, हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करे और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। युवा ही देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। युवाओं को सही दिशा प्रदान करने का कार्य केंद्र सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर किया जा रहा है। यह रोजगार मेला केवल नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

इस अवसर पर मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने बताया कि पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कुल 115 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इनमें 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी रेलवे विभाग से संबंधित थे तथा 29 महिला अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नियुक्त अभ्यर्थियों में रेलवे विभाग के 66, वित्तीय सेवा विभाग के 36, डाक विभाग के 09, आयकर विभाग के 02 तथा ईपीएफओ एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक-एक अभ्यर्थी शामिल हैं।

अहमदाबाद में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में माननीया युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री, भारत सरकार श्रीमती रक्षा निखिल खडसे, माननीय श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार तथा ग्रामीण विकास मंत्री, गुजरात सरकार श्री कुंवरजीभाई बावलिया, माननीया शहरी विकास एवं शहरी आवास राज्यमंत्री, गुजरात सरकार श्रीमती दर्शना बेन वाघेला, माननीय सांसद अहमदाबाद पश्चिम श्री दिनेशभाई मकवाणा, माननीय सांसद (राज्यसभा) श्री नरहरि अमीन, अहमदाबाद क्षेत्र के माननीय विधायकगण एवं मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

गिफ्ट सिटी बना भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत का नया प्रतीक

गांधीनगर। Nirmala Sitharaman ने शुक्रवार को कहा कि भारत आज दुनिया के सामने पैमाना, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और तीव्र आर्थिक वृद्धि के अवसरों का एक अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहा है और गुजरात में विकसित हो रहा GIFT City इस नई आर्थिक सोच का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी केवल एक वित्तीय केंद्र नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास, वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और आधुनिक वित्तीय संरचना का प्रतीक बन चुका है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी और वहां विकसित हो रहे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा परिवेश की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी आईएफएससी के विस्तार, वैश्विक निवेश, बैंकिंग, बीमा, फिनटेक, कोष प्रबंधन, विमान और जहाज पट्टे की व्यवस्था, बुनियादी ढांचा विकास तथा वैश्विक कारोबारी कनेक्टिविटी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद अपने संबोधन में सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट सिटी में अब तक जो प्रगति हुई है, वह अत्यंत उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, नियामक संस्थाओं और उद्योग जगत के बीच लगातार समन्वय के कारण यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है और गिफ्ट सिटी इसी परिवर्तन का एक प्रमुख केंद्र बनकर सामने आया है।

उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी भारत को वैश्विक वित्तीय बाजारों से जोड़ने में रणनीतिक भूमिका निभा रहा है। यहां तैयार किया जा रहा आधुनिक वित्तीय तंत्र अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को सुगम बना रहा है और विदेशी निवेशकों के लिए भारत को अधिक आकर्षक बना रहा है। उनके अनुसार भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल उपभोक्ता बाजार, तकनीकी क्षमता और युवा प्रतिभा के साथ जब गिफ्ट सिटी जैसी विश्वस्तरीय वित्तीय संरचना जुड़ती है, तब देश वैश्विक निवेश और वित्तीय गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि गिफ्ट सिटी अब केवल एक परियोजना नहीं रह गई है, बल्कि यह भारत की आर्थिक सोच और वैश्विक दृष्टि का प्रतिनिधित्व कर रही है। उन्होंने कहा कि यह शहर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भारत की नई पहचान बना रहा है। दुनिया के कई बड़े निवेशक और वित्तीय संस्थान अब भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय नवाचार और निवेश के केंद्र के रूप में देखने लगे हैं।

बैठक में प्रधानमंत्री Narendra Modi के प्रमुख सचिव P. K. Mishra भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण गिफ्ट-आईएफएससी को एक ऐसे विश्वस्तरीय वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करना है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, आधुनिक सुविधाओं और कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि गिफ्ट सिटी को बैंकिंग, बीमा और फिनटेक क्षेत्र में और अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए। इसके अलावा वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी की स्थापना, विमान और जहाज पट्टे से जुड़ी गतिविधियों का विस्तार, कारोबारी सुगमता बढ़ाने तथा वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने की रणनीति पर भी विचार किया गया।